CMYK

www.maharashtracrimes.in
Email : editor@maharashtracrimes.in

www.maharashtracrimes.blogspot.in
maharashtracrimes@gmail.com

RNI NO. : MAHHIN/1998/02261

महाराष्ट्र क्राईम्स

वर्ष 20 | अंक 02 | मुंबई, 05 दिसंबर 2021 | पृष्ठ : 8 | कीमत : 5 रुपये | प्रधान संपादक : सिराज चौधरी

अगर दादा से पंगा लिया तो...!

मुंबई मेयर और उनके परिवार को मिली जान से मारने की धमकी

मुंबईः मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को जान से मारने की धमकी मिली है. पिछले साल भी शिवसेना नेता पेडनेकर को धमकी मिली थी. मेयर को मराठी में लिखा एक पत्र मिला है जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है. पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर वह ह्लदादाह्व के साथ पंगा लिया तो परिणाम भुगतने होंगे. मुंबई के भायखला पुलिस थाने के अधिकारी मेयर के आवास पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है. पिछले साल पेडनेकर को फोन पर धमकी मिली थी. उन्होंने पुलिस को बताया था कि फोन करने वाले ने उसे बताया कि वह गुजरात के जामनगर से फोन कर रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दी है. पुलिस ने बाद में आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया था. पेडनेकर को नवंबर 2019 में बृहन्मुंबई नगर निगम के मेयर के रूप में निर्विरोध चुना गया था. वह और उप महापौर शिवसेना पार्षद सुहास वाडकरंद निर्विरोध चुने गए थे क्योंकि भाजपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे. बता दें, उसी साल शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस और राकांपा के साथ महा विकास अघाड़ी सरकार बनाई.

परिवहन मंत्री अनिल परब ने दी मेस्मा की चेतावनी

एसटी कर्मचारियों को अंतिम अल्टीमेटम !

मुंबई : विलीनीकरण की मांग को लेकर पिछले 44 दिनों से हड़ताल पर अड़े एसटी कर्मचारियों को सोमवार तक का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है। परिवहन मंत्री अनिल परब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यदि सोमवार तक हड़ताली कर्मचारी काम पर वापस आ जाते हैं, तो उनका निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि यह आखिरी अल्टीमेटम है।

अनिल परब ने कहा है कि काम पर आए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दी गई है। काम पर आने वालों को वेतन वृद्धि दी जाएगी। अनिल परब ने कहा कि सोमवार तक काम पर आने वाले कर्मचारियों को काम पर रखा जाएगा, इसके बाद निलंबन

की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को रोका गया तो उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाएगी।

अनिल परब ने कहा कि 2018 के नियमानुसार एसटी आवश्यक सेवा में आती है इसलिए मेस्मा के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। परब ने कहा कि मानवता की दृष्टि से कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल से अब तक एसटी को 550 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। परब ने कहा कि जो कर्मचारी एक महीने से काम पर नहीं थे, उन्हें उनका वेतन कैसे मिलेगा। इसके लिए नेता जिम्मेदार हैं, क्या वे नुकसान भरपाई करेंगे। परब ने कहा कि मैंने निगम के सभी अधिकारियों से बात की है, उनका कहना है कि कर्मचारी आने को तैयार हैं। 10 हजार कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन की कार्रवाई के चलते कुछ कर्मचारी ग्रुप में मिलने आ रहे हैं। हड़ताल को आत्महत्या से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। परिवहन मंत्री ने कहा कि विलय का मुद्दा समिति के समक्ष है। 12 सप्ताह में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इसके लिए तुरंत फैसला नहीं लिया जा सकता। परब ने कहा कि सदाभाऊ खोत और पडलकर ने हमारी भूमिका को स्वीकार किया, लेकिन वे कामगारों को समझाने में नाकाम रहे। ज्ञात हो कि ज्यादातर कामगार अभी भी विलीनीकरण पर अडिग हैं। एसटी के 93 हजार कर्मचारियों में लगभग 20 हजार काम पर लौट चुके हैं।

पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट से बड़ी राहत

संपत्ति जब्ती के संबंध में 10 जनवरी तक कार्रवाई नहीं करें

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के निर्णय लेने वाले प्राधिकारी धन शोधन के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और उनकी पत्न ी आरती देशमुख के संपत्ति की अस्थाई रूप से जब्त करने के बारे में सुनवाई कर सकता है और अंतिम आदेश भी पारित कर सकता है, लेकिन वह इस संबंध में 10 जनवरी तक कोर्द दंडात्मक कार्रवाई नही की जाए। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने ईडी को निर्देश दिया कि वह धन शोधन मामले में अपनी संपत्तियों के अस्थाई रूप से जब्ती के एजेंसी के आदेश को चुनौती देने वाली आरती देशमुख की याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अनिल देशमुख को इस संबंध में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। याचिका में आरती देशमुख ने दावा किया है कि वह अपनी संपत्तियों की अस्थाई रूप से जब्ती संबंधी सुनवाई के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एजेंसी इस संबंध में कानून का पालन नहीं कर रही है।

आरती के अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने इससे पहले दलील दी थी कि धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कानून के अनुरुप न्यायिक प्राधिकार तीन सदस्यीय होना चाहिए। इसमे एक अध्यक्ष और दो सदस्य होने चाहिए, जिनमें से एक कानूनी पृष्ठभूमि से होना चाहिए। चौधरी ने दलील दी, ''वर्तमान में इस प्राधिकार में सिर्फ एक सदस्य ही है, जिनकी कोई कानूनी पृष्ठभूमि नहीं है। पिछले सप्ताह जब याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था, तब पीठ ने कहा था कि प्राधिकार सुनवाई कर सकता है लेकिन उसे अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए। हालांकि, ईडी ने बाद में इस मामले का जिक्र किया और कहा कि आदेश पारित करने से पहले उच्च न्यायालय ने उसका पक्ष नहीं सुना था। शुक्रवार को ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि एक सदस्यीय प्राधिकार के पास भी कानून सुनवाई करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, ''हम याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठा रहे हैं।

CMYK

संपादकीय

परमाणु प्लांट पर पंगा

महाराष्ट्र के जैतापुर में छह परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की केंद्र सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी के एक दिन बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बिना कोई परियोजना जबरन लागू नहीं कर सकता है. परमाणु ऊर्जा विभाग में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में कहा कि सरकार ने फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग से 1,650-1,650 मेगावाट के छह परमाणु बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र में जैतापुर में स्थल की 'सिद्धांततः' मंजूरी प्रदान कर दी है जो 9,900 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ सबसे बड़ा परमाणु बिजली उत्पादन स्थल बन जाएगा. इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए राकांपा के प्रवक्ता एवं महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि विकास और नयी परियोजनाओं की आवश्यकता है लेकिन स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बिना नहीं. उन्होंने कहा, ''केंद्र सरकार स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बिना कोई परियोजना थोप नहीं सकती. जैतापुर परियोजना संप्रग सरकार लेकर आयी थी लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इसे रोकना पड़ा था.'' मलिक ने कहा कि हाल में तीन कृषि कानूनों को वापस लेना इसका उदाहरण है कि जब फैसले पक्षकारों से विचार-विमर्श किए बिना लिए जाते हैं, तो क्या होता है. शिवसेना नेता एवं सिंधुदुर्ग से लोकसभा सदस्य विनायक राउत ने दिल्ली में पत्रकारों से संसद में सरकार का जवाब तकनीकी था. उन्होंने कहा, ''मैंने पिछले कुछ वर्षों में कम से कम छह दफा इस तरह के जवाब देखे हैं. स्थानीय आबादी इस परियोजना के खिलाफ है जो हानिकारक है और इससे पूरी कोंकण तट रेखा पर असर पड़ेगा.'' राउत ने कहा कि शिवसेना इस परियोजना के विरोध में स्थानीय लोगों के साथ दृढ़ता से खड़ी है. उन्होंने कहा, ''आपको कोंकण में परमाणु ऊर्जा की क्या आवश्यकता है जबकि केंद्र सौर ऊर्जा का प्रचार कर रही है. कोंकण में सौर पार्क बनाए जा सकते हैं.''

कोरोना से मौतों पर मुआवजे में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, महाराष्ट्र-राजस्थान को दिया आदेश

मुंबई : कोविड से हुई मौत पर 50 हजार का मुआवजा देने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी दिखाई है.सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल समेत कई राज्यों को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के चीफ सेकेट्री को नोटिस जारी कर मुआवजे का ब्योरा मांगा है. उनसे कुल मौतों, प्राप्त दावों, भुगतान किए गए दावों पर स्टेटस रिपोर्ट दर्ज दाखिल करने को कहा है. मामले में 17 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.सुनवाई के दौरान जस्टिस एम आर शाह ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि आपने केवल 8,000 को मुआवजा दिया है. आपके राज्य में 1.41 लाख से अधिक मौते हुई हैं. महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हमारे यहां संख्या भी अधिक है. 1.41 लाख

मौतें हुई हैं और एक लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं. 12 हजार लोगों को मुआवजा दे दिया गया है. एक हफ्ते में बाकी को भी दे देंगे. जस्टिस शाह ने कहा कि लेकिन 1.41 लाख सिर्फ दर्ज मौतें हैं. संख्या बढ़ेगी ही ये साफ है. अदालत ने आदेश दिया कि हमारी पिछली कड़ी टिप्पणियों के बावजूद केवल 8,000 दावेदारों को भुगतान किया गया है. महाराष्ट्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि शेष दावेदारों को भुगतान आज से एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा. सरकार को आज से एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने का दिया जाता है. ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. राजस्थान के वकील ने कहा कि 8,955 मौतें दर्ज की गई हैं. इनमें से 8,577 को मुआवजा दिया गया है. हमने 95% से अधिक लोगों को मुआवजा दिया है. जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि कौन विश्वास करेगा कि पूरे राजस्थान में केवल 8,955 लोगों की मौत हुई? आप हमें यह भी नहीं बता सकते कि आपको कितने आवेदन मिले. इसका मतलब है कि आप किसी चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं.

मुंबई एनसीबी में समीर वानखेड़े का कार्यकाल समाप्त हुआ

वापस मूल संगठन डीआरआई भेजे गए

मुंबई : स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई के विवादों में रहे क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े का संघीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसी में कार्यकाल समाप्त हो गया है और उन्हें वापस उनके मूल संगठन ह्यडीआरआईह्व में भेज दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई का अतिरिक्त प्रभार एजेंसी के इंदौर क्षेत्रीय निदेशक बृजेंद्र चौधरी संभालेंगे। भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 2008 बैच के अधिकारी वानखेड़े को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ पहलू की एजेंसी द्वारा की जा रही जांच के मद्देनजर अगस्त 2020 में राजस्व

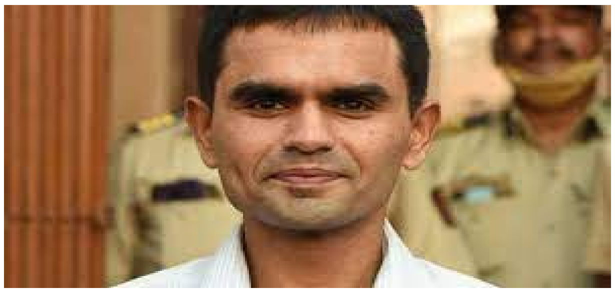

खुफिया निदेशालय (डीआरआई) में भेजा गया था। वानखेड़े, 31 अगस्त 2020 से एनसीबी की मुंबई इकाई में क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर सेवा दे रहे थे और उनके कार्यकाल को कुछ समय के लिए बढ़ाया भी गया था। अधिकारियों ने बताया कि एनसीबी में वानखेड़े का विस्तारित कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया और चूंकि उनके कार्यकाल में विस्तार का आदेश नहीं दिया गया है, इसलिए उन्हें उनके मूल संगठन डीआरआई में भेज दिया गया है, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के तहत एक अन्वेषण एजेंसी के तौर पर काम करता है। पिछले साल अक्टूबर में एनसीबी द्वारा मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापा मारने की कार्रवाई करने के बाद वानखेड़े चर्चा में रहे थे। छापे के दौरान अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान और कई अन्य को गिरफ्तार किया गया था। इस कार्रवाई के शीघ्र बाद महाराष्ट्र में मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने उनके खिलाफ कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। इससे पहले, एनसीबी ने वानखेड़े के नेतृत्व के तहत, राकांपा नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान को मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार किया था।

Avenue Spa
Rejuvenate Your Body Mind & Soul
SPECIAL CHRISTMAS OFFER
999/-
022-27700160
9137758221
Shop No.F-27, Haware Centurion Mall, 1st floor, Plot No.88/91, Sector-19A, Seawoods (E) Navi Mumbai.

महंगाई का झटका: मुंबई में बढ़ेंगे सीएनजी और पीएनजी के दाम

मुंबई : मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें फिर बढ़ने जा रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 दिसंबर की मध्यरात्रि से मुंबई में सीएनजी की कीमत दो रुपये/एससीएम और पीएनजी की कीमत 1.50 रुपये/एससीएम बढ़ जाएगी। कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर आम आदमी पर जरूर पड़ेगा। 4 दिसंबर को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली,

हरियाणा और राजस्थान में सीएनजी की कीमतों में वृद्धि की थी। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रति किलोग्राम सीएनजी की खुदरा लागत 53.04 रुपये पहुंच गई थी।

मुंबई लोकल ट्रेन में बिना टिकट के सफर करने वालों पर रेलवे की कार्रवाई

नवंबर तक वसूले 18.70 करोड़ रुपये का फाइन

मुंबई : कोरोना की दूसरी लहर में देश के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक मुंबई में अनलॉक के बाद से शहर में पाबंदियों में ढील दी गई है। इसके साथ ही मुंबई की लाइफलाइन कही जानेवाली लोकल ट्रेन में एक बार फिर से भीड़ बढ़ने लगी है। लोकल ट्रेनों में लगातार बढ़ती भीड़ के बाद रेलवे भी अलर्ट पर है और बिना टिकट के यात्रा करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे ने मुंबई में नवंबर महीने में रिकॉर्ड कार्रवाई की है। पश्चिम रेलवे के अनुसार, मुंबई लोकल ट्रेनों में बिना टिकट सफर करने के नवंबर महीने में कुल 2.81 लाख मामले सामने आए हैं। इन सभी मामलों में बतौर

फाइन रेलवे ने 18.70 करोड़ रुपये वसूले हैं। पश्चिम रेलवे ने ट्वीट करते हुए अपने इस विशेष रिकॉर्ड की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि, पश्चिम रेलवे ने अप्रैल से नवंबर 2021 तक चलाए गए टिकट जांच अभियान के दौरान कर्मचारियों ने बिना टिकट/अनियमित यात्रा के 9.60 लाख मामलों में बिना बुक किए सामान के मामलों में कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप रुपये की वसूली हुई. 55.28 करोड़।

बता दें कि, मुंबई में कोरोना पाबंदियों में अब ढील दी जा रही है। इसके बाद से शहर में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के चलते बंद हुए बिजनेस और ओफिसिस एक बार फिर से खोले जा चुके हैं। ऐसे में अब वर्क फ्रॉम होम ज्यादातर जगह बंद हो चूका है जिसके बाद लोग अलग-अलग ट्रांसपोर्ट के जरिए कम पर जा रहे हैं। वहीं मुंबई की लाइफ लाइन कही जानेवाली मुंबई लोकल ट्रेन में भी अब भीड़ बढ़ने लगी है।

वहीं कोरोना महामारी के चलते आम लोगों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन बंद गई थीं। ट्रेनों को बीते 15 अगस्त को पूरी तरह से टीका लगाए गए यात्रियों के लिए सेवाएं फिर से शुरू हुई थीं।

रेशमा खान केस: महाराष्ट्र के एडीजी भारती के खिलाफ एफआईआर

बांग्लादेशी महिला पर केस नहीं चलाने का आरोप

मुंबई : एक बांग्लादेशी महिला के खिलाफ केस नहीं चलाने पर महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेश देवेन भारती और एक अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला बांग्लादेशी महिला रेशमा खान के मामले से जुड़ा है। उस पर धोखाधड़ी से भारतीय पासपोर्ट हासिल करने का आरोप है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मालवणी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में भारती और सहायक पुलिस आयुक्त दीपक फटगारे के अलावा महिला रेशमा खान का नाम है। रेशमा खान उत्तर मुंबई के मालवणी इलाके में रहती है। वह कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में घुसी थी। उसने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से मुंबई में भारतीय पासपोर्ट बनवा लिया।

कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि रेशमा खान ने एक

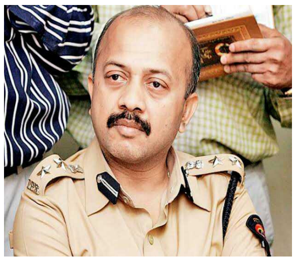

स्थानीय भाजपा नेता से शादी की थी। कुछ सप्ताह पूर्व महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने इस मामले को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था। 2017 में मुंबई पुलिस की विशेष शाखा के तत्कालीन इंस्पेक्टर दीपक कुरुलकर ने एक जांच में पाया था कि रेशमा खान भारतीय नागरिक नहीं है। इसके बाद कुरुलकर ने मालवणी पुलिस थाने से उसके खिलाफ केस दर्ज करने को कहा था।

कुरुलकर की शिकायत के आधार पर वरिष्ठ इंस्पेक्टर दीपक फटगारे ने मालवणी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं की। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कुरुलकर ने यह भी आरोप लगाया था कि एडीजी देवेन भारती, जो कि उस वक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व व्यवस्था थे, ने एफआईआर दायर नहीं करने के लिए दबाव डाला था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारती व दो अन्य के खिलाफ इसी सप्ताह भादंवि की धारा 465, 420 और 34 के तहत केस दर्ज किया है। इसके अलावा पासपोर्ट एक्ट और विदेशी नागरिक कानून की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मामला क्राइम ब्रांच पुलिस की अपराध गुप्तचर इकाई को सौंप दिया गया है। वह एफआईआर में नामजद अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगी। अधिकारी ने बताया कि हम रेशमा खान की गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश उपाध्यक्ष हिंदूवादी नेता पवन सोलंकी ने 15 सालों में हजारों लोगों की मदद कर लाखों लोगों का दिल जीता

भोपाल : भोपाल मध्यप्रदेश उपाध्यक्ष हिंदूवादी नेता पवन सोलंकी जिन्होंने 5 जनवरी 2004 से समाज सेवा आरंभ की और 5 नवंबर 2021 तक हजारों गायों की जान बचाई पवन सोलंकी ने अभी तक भोपाल इंदौर उज्जैन देवास रतलाम नीमच मंदसौर सीहोर धार खरगोन अलीराजपुर बुरहानपुर जैसे अनेकों जिलों में बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए गौ माता के सींग पर लाल रेडियम लगाया था ताकि कोई बड़ा रोड़ हादसा ना हो इस लाल रेडियम से रात्रि में चल रहे वाहन चालक को दूर से ही पता चल जाता हैं की रोड़ स्थित गौ माता बैठी हुई हैं। हिन्दूसंगठन मध्यप्रदेश उपाध्यक्ष पवन सोलंकी ने महावीर जयंती के दिन एक महिला को बचाया जो कलेक्टर बंगले के बाहर आत्महत्या कर रहीं थी आपको बता दें कि महिला अपने साथ हुई घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराने चार बार थाने गई लेकिन थाना दूसरा लगना बता कर महिला की रिपोर्ट दर्ज नहीं कि पवन सोलंकी ने तत्काल एसपी से बात कर महिला की तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराई मध्यप्रदेश उपाध्यक्ष पवन सोलंकी ने कोरोना महामारी में बेसहारा परिवारो को 10000 दस हजार खाने के पैकेट बाटे गरीब बच्चों में 4000 चार हजार किताबें बाटी हैं इंडिया बुल्स नामक कंपनी में 200 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हुई थीं उन सभी पीड़ित महिलाओं की कलेक्टर आईजी से बात कर तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराई एक्सीडेंट में घायल हुए उन सभी लोगों को पवन सोलंकी ने होस्पिटल पहुचाया गौ माता की रक्षा के लिए आएं दिन पवन सोलंकी चेकिंग अभियान चलाते हैं बीच रोड़ पर बैठी गायों को भी स्वयंम हटाते हैं ताकि कोई बड़ा रोड़ हादसा न हो राखी दीवाली जैसे त्यौहारो पर पवन सोलंकी ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे पवन सोलंकी ने 15 साल की जनसेवा में कई मुख्य सचिव डीजीपी जैसे बड़े अधिकारियों का भी सम्मान किया है मध्यप्रदेश उपाध्यक्ष पवन सोलंकी जिन्होंने सन 2004 से 2021 तक हजारों लोगों की मदद कर लाखों लोगों का दिल जीता है । इनका यह प्रयास आगें भी जारी रहेगा

महिला मित्र ने फोन नहीं उठाया तो युवक ने की खुदकुशी,

लेट नाइट पार्टी से लौटे थे दोनों

मुंबई: एक युवक ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसकी महिला मित्र ने उसका फोन नहीं उठाया. बताया जा रहा है कि मुंबई के देवनार इलाके में एक 24 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. हत्या के पीछे का कारण उसकी महिला मित्र का फोन नहीं उठाया जाना बताया जा रहा है.

मृतक की पहचान मानव लालवानी के रूप में हुई है. ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के अधिकारी सिद्धेश्वर गोवे ने बताया कि युवक और उसकी महिला मित्र दोस्तों के साथ देर रात पार्टी में शामिल हुए थे. पार्टी खत्म होने के बाद घर पहुंचने पर युवक ने फोन पर उससे संपर्क करने की कोशिश की. लेकिन महिला ने फोन नहीं उठाया. लेकिन जब फोन पर बात नहीं हो पाई तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

मंगलवार सुबह उसके माता-पिता ने उसे छत पर लटका पाया और पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने पीड़िता के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. आगे की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. मामला दर्ज कर लिया गया है और महिला का बयान भी लिया गया है.

पालघर जिले के अनार्ला में दोस्त की हत्या के आरोप में दो शख्स गिरफ्तार

पालघर : पालघर जिले के अनार्ला से पुलिस ने पैसों के लेन-देन को ले कर अपने दोस्त की हत्या करने के आरोप में दो मजदूरों को गिरफ्तार किया है।एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आरोपियों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया। अनार्ला सागरी पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक राजू माने ने कहा, 10 दिसंबर को अरनाला में एक कुएं के पास से 40 साल की आयु के आसपास के एक अज्ञात शख्स का क्षत विक्षत शव मिला।शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस को यह पता चला कि मृतक को आखिरी बार विरार के डोंगरापाड़ा में एक व्यक्ति के साथ देखा गया था जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि बाद में मृतक की पहचान हरीश नाथू पडाल के रूप में की गयी जो एक खेत में मजदूरी करता था और मत्स्य पालन के कारोबार में भी शामिल था। अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध को हिरासत में लिए जाने के बाद यह पता चला कि आरोपी, पीड़ित तथा एक और शख्स अतिरिक्त कमायी के लिए मत्स्य पालन के कारोबार में भी शामिल थे। पैसों के बंटवारे को लेकर आए दिन उनका झगड़ा होता रहता था। उन्हें शराब पीने की भी लत थी। माने ने कहा, घटना के दिन पीड़ित और दो अन्य आरोपियों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर बहस हुई। गुस्से में आकर दोनों आरोपियों ने पीड़ित के सिर पर किसी सख्त चीज से वार कर दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गयी। बाद में उन्होंने शव कुएं के पास एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) तथा अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

कोरोना से मौतों पर मुआवजे में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, महाराष्ट्र-राजस्थान को दिया आदेश

मुंबई : कोविड से हुई मौत पर 50 हजार का मुआवजा देने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी दिखाई है.सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल समेत कई राज्यों को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के चीफ सेकेट्री को नोटिस जारी कर मुआवजे का ब्योरा मांगा है. उनसे कुल मौतों, प्राप्त दावों, भुगतान किए गए दावों पर स्टेटस रिपोर्ट दर्ज दाखिल करने को कहा है. मामले में 17 जनवरी को अगली सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान जस्टिस एम आर शाह ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि आपने केवल 8,000 को मुआवजा दिया है. आपके राज्य में 1.41 लाख से अधिक मौते हुई हैं.

महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हमारे यहां संख्या भी अधिक है. 1.41 लाख मौतें हुई हैं और एक लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं. 12

हजार लोगों को मुआवजा दे दिया गया है. एक हफ्ते में बाकी को भी दे देंगे. जस्टिस शाह ने कहा कि लेकिन 1.41 लाख सिर्फ दर्ज मौतें हैं. संख्या बढ़ेगी ही ये साफ है. अदालत ने आदेश दिया कि हमारी पिछली कड़ी टिप्पणियों के बावजूद केवल 8,000 दावेदारों को भुगतान किया गया है. महाराष्ट्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि शेष दावेदारों को भुगतान आज से एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा. सरकार को आज से एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने का दिया जाता है. ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. राजस्थान के वकील ने कहा कि 8,955 मौतें दर्ज की गईं हैं. इनमें से 8,577 को मुआवजा दिया गया है. हमने 95% से अधिक लोगों को मुआवजा दिया है. जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि कौन विश्वास करेगा कि पूरे राजस्थान में केवल 8,955 लोगों की मौत हुई? आप हमें यह भी नहीं बता सकते कि आपको कितने आवेदन मिले. इसका मतलब है कि आप किसी चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं. राजस्थान के वकील ने इस पर सफाई दी कि हमारे पास मौतों का डेटा था इसलिए हमने उसी के अनुसार मुआवजा दिया. राजस्थान का कहना है कि उसके पास अब तक किए गए कितने दावों का कोई डेटा नहीं है. प्रदेश में सीधा व्यापक प्रचार हो. अब तक कितने दावे प्राप्त हुए, इसकी जानकारी दी जाए.

इंद्राणी मुखर्जी ने किया दावा, शीना बोरा जिंदा है, सीबीआई कश्मीर में करे तलाश

मुंबई : अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया है कि वह (शीना) जिंदा है। मुखर्जी के वकील ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। मुखर्जी ने पिछले महीने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक को एक पत्र लिखा है और एजेंसी से कहा है कि वह कश्मीर में शीना की तलाश करे। मुखर्जी ने पत्र में दावा किया है कि एक महिला सरकारी अधिकारी ने उससे कहा है कि उसने बोरा को श्रीनगर में टीकाकरण कराने के दौरान देखा था। इंद्राणी 2015 से मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद है। संपर्क करने पर सीबीआई के एक अधिकारी ने इसपर टिप्पणी करने

से इनकार कर दिया है। वकील ने कहा कि मुखर्जी 28 दिसंबर को यहां विशेष सीबीआई अदालत में इस संबंध में एक आवेदन दायर करेंगी। उसी दिन मामले की सुनवाई की अगली तारीख है। विशेष अदालत हाई प्रोफाइल हत्याकांड की सुनवाई कर रही है। शीना बोरा (24) की मुखर्जी और उसके तत्कालीन चालक श्यामवीर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने अप्रैल 2012 में एक कार में कथित रूप से गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

१,५१७ अस्पताल, नर्सिंग होम की हुई जांच, २० निजी अस्पतालों पर गिरी गाज

मुंबई : अस्पतालों में आग लगने से होनेवाले जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए मनपा के फायर ब्रिगेड की ओर से मुंबईभर में सभी अस्पताल, नर्सिंग होम की जांच की जा रही है। इस अभियान के तहत १,५१७ निजी अस्पतालों के सर्वेक्षण में २० अस्पतालों में अग्निसुरक्षा यंत्रणा को लेकर खामियां पाई गईं। मनपा के निदेशों के बाद भी इन अस्पतालों ने कोई सुधार नहीं किया। अब इन पर मनपा की गाज गिरी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। कुछ अस्पतालों एवं नर्सिंग होम के बिजली व पानी का कनेक्शन काट दिया गया है और गेट पर ताले लटका दिए गए हैं।

फंड मिलने के मामले में सीएम पद वाली शिवसेना फिसड्डी, NCP सबसे आगे, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना के हैं, लेकिन फंड मिलने के मामले में महा विकास आघाडी गठबंधन की तीनों पार्टियों में से एक शिवसेना सबसे फिसड्डी है. फंड मिलने के मामले में शिवसेना कांग्रेस से भी पीछे है. शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फंडिंग के मामले में सबसे आगे है. राज्य में वित्त विभाग एनसीपी के पास ही है. साल 2020 से 2021 तक के फंड आवंटन के आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा विधायक और मुख्यमंत्री पद वाली शिवसेना पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है. महा विकास आघाडी सरकार में दूसरे नंबर पर रहने वाली एनसीपी फंड हासिल करने में आगे चल रही है. बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे के पर्यावरण विभाग को भी फंड

मिलने में मुश्किल हो रही है.

फंड के बंटवारे से पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे पर गहरा असर पड़ा है. कुल 420 करोड़ रुपये के आवंटन में से सिर्फ तीन फीसदी यानी 14 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत महा विकास आघाडी सरकार की स्थापन हुई थी. शरद पवार के पास सरकार चलाने का अनुभव है, इसलिए ऐसा लगता है कि तीनों पार्टियों को एकजुट करने से सबसे ज्यादा फायदा एनसीपी को हुआ है.

सिर्फ राष्ट्रवाद का राग अलापती है शिवसेना

सेक्युलरिज्म से मुसलमानों को क्या मिला - असदुद्दीन ओवैसी

मुंबई : मुस्लिम आरक्षण की मांग और वक्फ बोर्ड की जमीन की बंदरबांट को रोकने की मांग को लेकर शनिवार को अक्टक्ट ने तिरंगा यात्रा निकाली। औरंगाबाद से शुरू हुई यह यात्रा मुंबई के चांदिवली पहुंची, जहां एक सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में अक्टक्ट के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, चुनाव आने पर चुनाव आया, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्मङ्क्या मिला मुसलमानों को सेक्युलरिज्म से? इससे आरक्षण मिला? हक मिला? इंसाफ मिला? राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण की मांग पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी सरकार गंभीर नहीं है। इसने मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर किया है और बदले में इस कौम को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं दिया है। ओवैसी ने कहा कि, चुनाव आने पर चुनाव आया, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्मङ्क्या मिला मुसलमानों को सेक्युलरिज्म से? इससे आरक्षण मिला? हक मिला? इंसाफ मिला?

संजय राउत ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिल कर उत्तर प्रदेश और गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ने की

बीएमसी चुनाव: शिवसेना और एनसीपी साथ, कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव!

मुंबई : शिवसेना के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिल कर उत्तर प्रदेश और गोवा में विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने के बारे में बात की है। लेकिन दिलचस्प जानकारी यह है कि अगले साल के शुरू में महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनावों में दोनों पार्टियां अलग लड़ने की तैयारी कर रही हैं।

अगले साल के शुरू में बृहन्न मुंबई महानगरपालिका पुणे और कुछ अन्य बड़े शहरों में नगर निगम के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में दोनों पार्टियां अकेले लड़ सकती हैं।

हालांकि अगले कुछ दिन में राहुल गांधी मुंबई जाने वाले हैं, जहां उनकी उद्धव ठाकरे से बातचीत होगी और इस बारे में अंतिम फैसला होगा लेकिन अभी यह कहा जा रहा है कि दोनों अलग लड़ेंगे।

जानकार सूत्रों के मुताबिक बीएमसी के चुनाव में शिव सेना और एनसीपी एक साथ लड़ेंगे और कांग्रेस अकेले लड़ेगी। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि शिव सेना हर हाल में अपने कट्टर हिंदू मतदाताओं को साथ रखना चाहती है और इसके अलावा मराठा मतदाताओं को भी जोड़े रखना चाहती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के साथ होने से कट्टर हिंदू मतदाता भाजपा की ओर मुड़ सकते हैं। शरद पवार की एनसीपी भी अपने को सेकुलर पार्टी बताती है लेकिन हिंदू और मराठी मतदाताओं के बीच उसके प्रति वैसा भाव नहीं है, जैसा कांग्रेस के प्रति है।

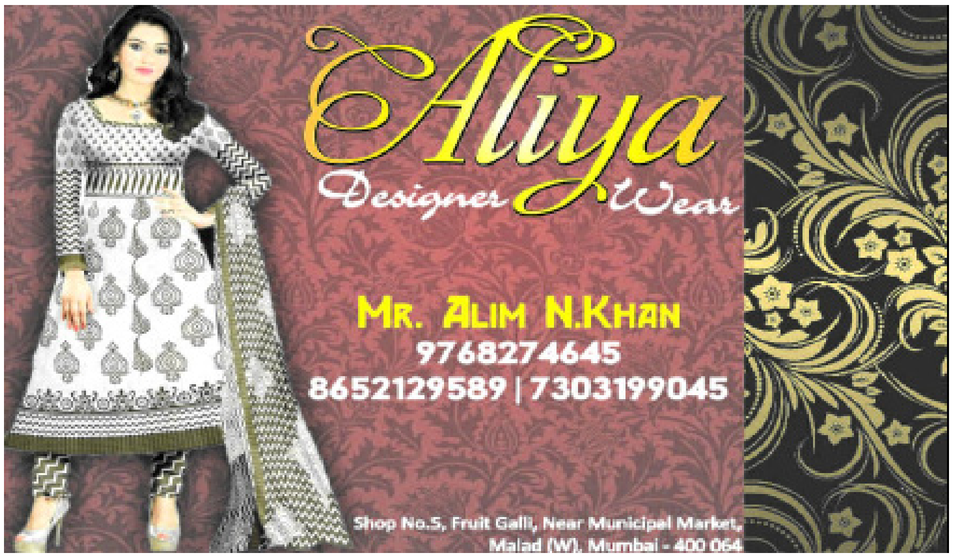

CMYK

ईडी की तरफ से अफवाह फैलाना हो बंद

सरकारी मेहमानों का करेंगे स्वागत- मलिक

मुंबई : राकांपा मुख्य प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से खबर चल रही है कि उनके घर पर ईडी द्वारा छापा मारा जाएगा। ऐसी अफवाहें फैलाना बंद होना चाहिए। भाजपा के एजेंडे पर हमें बदनाम करने की कोशिश बंद होनी चाहिए। इसके पहले मलिक ने ट्वीट कर कहा था कि साथियों सुना है, मेरे घर आजकल में सरकारी मेहमान आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करेंगे।

मलिक ने कहा कि डरना मतलब रोज-रोज मरना, हमें डरना नहीं, लड़ना है। हम वक्फ बोर्ड की जांच के लिए दस्तावेज देने को तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों से ईडी अधिकारी पत्रकारों को जानकारी दे रहे हैं कि नवाब मलिक के घर छापेमारी होगी। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि पुणे के वक्फ बोर्ड जमीन मामले में ईडी मेरे घर जाने वाली है। मलिक ने कहा कि ईडी बताए कि वह छापा मारने कब आ रही है, उसका पुष्पगुच्छ लेकर स्वागत करने का इंतजार कर रहा हूं। पुणे के वक्फ जमीन मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। ईडी ने वक्फ बोर्ड के एक अधिकारी को बुलाया था। इस अधिकारी ने ईडी अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई।

बिस्तर पर आघाड़ी सरकार-नारायण राणे

मुंबई : केंद्रीय लघु, सुक्ष्म व मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार पूरी तरह से बिस्तर पर ही है। यह सरकार बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रही है, जिसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। नारायण राणे ने मुंबई में शनिवार को पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार के निकम्मेपन की वजह से हर वर्ग परेशान है। राज्य में विकास के हर काम ठप हैं। इसके विपरीत केंद्र सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। उन्होंने अपने विभाग के काम के लिए कई राज्यों का दौरा भी किया है। महाराष्ट्र में उनके विभाग से अधिक से अधिक लोगों को उद्योग धंधे मिल सकें, इसका प्रयास जारी है। नारायण राणे ने शिवसेना प्रवक्ता संजय राऊत पर तंज कसते हुए कहा कि पता ही नहीं चलता कि वे शिवसेना में हैं या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में । संजय राऊत दिल्ली में हमेशा शरद पवार के घर में ही पाए जाते हैं। संजय राऊत देश को दिशा देने की बजाय सिर्फ झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं।

शरद पवार के भाषण पर आधारित किताब का विमोचन

'यह किताब मोदी को गिफ्ट देनी चाहिए'-शिवसेना सांसद राऊत

मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद शरद पवार के 81वें जन्मदिन के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार और मासिक पत्रिका ''राष्ट्रवादी'' के संपादक डॉ. सुधीर भोंगले ने शरद पवार के कुछ चुनिंदा भाषण का संकलन एक पुस्तक ह्यनेमकचि बोलणेंह्न में किया है। इस किताब का विमोचन शनिवार को वर्ली स्थित नेहरू सेंटर में किया गया। इस पुस्तक में शरद पवार के वर्ष 1988 से लेकर 1996 तक के 61 भाषणों को संकलित किया गया है। पुस्तक विमोचन समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में शिवसेना सांसद संजय राऊत उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक का नाम इतना अच्छा है कि हम सभी को इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में देना चाहिए। कार्यक्रम में राऊत के अलावा वरिष्ठ साहित्यकार रंगनाथ पठारे (वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से), डॉ. विजय केलकर, अनंत बागाईतकर, किशोर कदम, मनस्विनी लता रविंद्र, चिन्मयी सुमित, संदीप मेहता, शंभू पाटिल, राकांपा के कोषाध्यक्ष हेमंत टकले, लेखक डॉ. सुधीर भोंगले मंच पर उपस्थित थे। इसके अलावा शरद पवार, प्रतिभा पवार, मंत्री छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, जयंत पाटिल, नवाब मलिक, बालासाहेब थोरात, महापौर किशोरी पेडणेकर, सांसद सुप्रिया सुले आदि उपस्थित थे। शिवसेना सांसद संजय राऊत ने कहा कि राकांपा प्रमुख शरद पवार ने 25 साल पहले ही कहा था कि भाजपा एक विभाजनकारी पार्टी है, लेकिन शिवसेना को इस सच्चाई का अहसास दो साल पहले ही हुआ। पुस्तक के शीर्षक का उल्लेख करते हुए राउत ने कहा कि पुस्तक का नाम इतना अच्छा है कि हम सभी को इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में देना चाहिए। उन्हें कुछ चीजें जानने की जरूरत है। राउत ने कहा कि संसद का केंद्रीय सभागार पार्टियों के नेताओं और वरिष्ठ पत्रकारों के अलावा अन्य राजनेताओं के बीच बैठकों के लिए जाना जाता था, जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। उन्होंने कहा कि हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि संसद में सवाल पूछने की कोशिश करने वालों का विरोध किया जा रहा है और उन्हें दबाया जा रहा है। राउत ने कहा कि सवाल उठाने के बुनियादी अधिकारों से इंकार बहुसंख्यकवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि पवार ने कुछ साल पहले यह कहा था और अब हमने इसे वास्तविकता के रूप में देखा है।

सीबीडी बेलापुर पुलिस ने मतदाता कार्ड प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में 22 के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया

नवी मुंबई : सीबीडी बेलापुर पुलिस ने मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 22 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। बेलापुर निर्वाचन क्षेत्र के उप तहसीलदार (चुनाव) ने भौतिक सत्यापन के दौरान इन 22 व्यक्तियों द्वारा नए मतदाता कार्ड के पंजीकरण के लिए जमा किए गए बिजली के बिल को पते के प्रमाण के रूप में फर्जी पाया। पुलिस ने कहा कि भौतिक सत्यापन के दौरान बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) को दस्तावेजों में उल्लिखित पते और उस पते पर रहने वाले लोगों में विसंगतियां मिलीं । बीएलओ ने पाया कि ये लोग बिजली बिल में उल्लिखित पते पर उपलब्ध नहीं थे, ''सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा।

बेलापुर निर्वाचन क्षेत्र के तहसीलदार प्रभारी (चुनाव) राजश्री पेडनेकर ने एमएसईडीसीएल के साथ बिजली बिलों का सत्यापन किया और पाया कि आवेदकों द्वारा दस्तावेज जाली थे और पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। नए मतदाता कार्ड के पंजीकरण और मौजूदा कार्ड में सुधार के लिए एक विशेष अभियान 5 दिसंबर को समाप्त हुआ। तहसील कार्यालय के अनुसार, नए मतदाता कार्ड के लिए, आवेदकों को फॉर्म 06 जमा करने और राशन कार्ड, बिजली बिल जैसे निवास का प्रमाण संलग्न करने की आवश्यकता थी। संपत्ति कर रसीद, गैस कनेक्शन, दूसरों के बीच में।

नए मतदाताओं के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, सरकार ने भारत के चुनाव आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) नामक एक ऑनलाइन सेवा शुरू की है। व्यक्ति नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर अपना नया वोटिंग पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कर सकता है। सभी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, एक बीएलओ नियुक्त किया जाता है जो भौतिक सत्यापन के लिए फॉर्म में उल्लिखित पते पर जाता है। बीएलओ की प्रतिक्रिया के आधार पर, एनवीएसपी पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए एक और निर्णय लिया जाता है, ''अधिकारी ने कहा। हालांकि बीएलओ और मतदाता पंजीकरण कार्यालय ने इन 22 आवेदकों के बिजली बिल फर्जी पाए।

पुलिस के अनुसार, सभी 22 आवेदक नेरुल और सीवुड्स के निवासी हैं और उन्होंने कथित तौर पर फर्जी बिजली बिल जमा किए थे। इनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून 1950, 1951 और 1989 की धारा 419, 465, 468, 471 और धारा 31 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नवी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने बालू की तस्करी के आरोप में 3 लोग को किया गिरफ्तार

पनवेल : नवी मुंबई क्राइम ब्रांच (यूनिट 3) ने शुक्रवार सुबह पनवेल में बेचने के लिए पुणे से एक सैंड बोआ सांप की तस्करी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया था। गिरफ्तार लोगों की पहचान अरबाज शेख (24), सागर शिंदे (22) पुणे निवासी और रायगढ़ निवासी शाशा अली पठान (22) के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सरीसृप को पुणे के एक जंगल में पकड़ा और किसी को बेचने के लिए पनवेल ले गए। सैंड बोआ सहित वन्य जीव जंतुओं को अवैध रूप से पकड़ने और व्यापार करने पर प्रतिबंध है। अपराध शाखा के वरिष्ठ निरीक्षक शत्रुघ्न माली ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग शहर में एक लुप्तप्राय जानवर को बेचने के लिए ला रहे हैं। पुलिस ने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 और 511 और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 51 और 52 के तहत मामला दर्ज किया। बाद में उन्होंने अदालत से अनुमति लेने के बाद वन विभाग को रेत बोआ सौंप दिया।

एशियाई खेलों के लिये घुड़सवारी ट्रायल्स मुंबई में 12 से 16 दिसंबर तक

मुंबई : पहली बार 2022 एशियाई खेलों के लिये घुड़सवारी ट्रायल्स यहां 12 से 16 दिसंबर तक एमेच्योर राइडर्स क्लब (एआरसी) में कराये जायेंगे। 'शो जंपिंग' चयन ट्रायल्स महालक्ष्मी रेस कोर्स पर कराये जायेंगे जिसमें 16 साल और इससे अधिक उम्र के प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं।

भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआई) द्वारा आयोजित ट्रायल्स में दिल्ली, बेंगलुरू, चेन्नई के साथ मेजबान शहर मुंबई के घुड़सवार भाग लेंगे। इसमें टीमों और व्यक्तिगत स्पर्धाओं के लिये दो दौर में ट्रायल्स 'शो जंपिंग 1.40 मीटर' और 'शो जंपिंग 1.50 मीटर' वर्गों में कराये जायेंगे। यह पहली बार है जब मुंबई घुड़सवारी एशियाई खेलों के दूसरे और तीसरे दौर के ट्रायल्स करायेगा जो क्रमशः दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में कराये जायेंगे।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ कोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े

टिप्पणियों पर रोक लगाए जाने की मांग

मुंबई : एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े व उनकी पत्नी क्रांति रेडकर ने कोर्ट का रुख किया है। दोनों ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक कंटेंट पब्लिश किए जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। बॉम्बे सिविल कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में अपील की गई है कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर अपमान व आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर कंपनियों को निर्देशित किया जाए।

समीर वानखेड़े ने इस याचिका में कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, वे सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अब उन्होंने इसमें उनकी पत्नी को भी घसीट लिया है। उनके खिलाफ भी आपत्तिजनक, झूठी व बेबुनियाद टिप्पणियां प्रसारित की जा हरी हैं। दोनों ने मांग की है कि कोर्ट की ओर से सोशल मीडिया कंपनियों को इन पर रोक लगाने का निर्देश दे।

नवाब मलिक को लगाई थी फटकार

कोर्ट ने संबंधित मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक को फटकार लगाई थी। दरअसल, आर्यन खान ड्रग्स केस के बाद से नवाब मलिक समीर वानखेड़े व उनके परिवार को लेकर ट्विटर पर लगातार टिप्पणियां कर रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि, मलिक समीर वानखेड़े व उनके परिवार को लेकर सीधे तौर पर या इशारों में भी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे।

मुंबई के धारावी में ओमीक्रोन की दस्तक

तंजानिया से लौटा शख्स पाया गया पॉजिटिव

मुंबई : कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमीक्रोन की कई देशों में दहशत के बीच महाराष्ट्र में टेंशन बढ़ गई है। मुंबई के धारावी इलाके में ताजा ओमीक्रोन का मामला सामने आया है। मुंबई के धारावी इलाके से मिले केस में एनएनआई ने बीएमसी के हवाले से जानकारी दी है कि, व्यक्ति तंजानिया से लौटा था, वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती।

बता दें कि, महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरियंट ओमीक्रोन ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ओमीक्रोन से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां और भी तेज कर दी है। राहत की बात यह है कि मुंबई में कोरोना के नए केस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 7 दिन की बात की जाए तो करीब 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। साथ ही जो मामले दर्ज भी हो रहे हैं, उनमें से अधिकतर

मरीज असिम्प्टोमैटिक हैं। वहीं राज्य में ओमीक्रोन की दहशत के बीच शुक्रवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने राहत देने वाली जानकारी देते हुए बताया है कि, पुणे में कोरोना वायरस के नये स्वरूप ओमीक्रोन से संक्रमित मिले सात में से पांच मरीजों की जांच रिपोर्ट अब नेगेटिव आयी है। जिले में कोविड-19 की स्थिति पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि पिम्परी-चिंचवाड़ औद्योगिक टाउनशिप में मिले छह में से चार मरीजों और पुणे शहर के एक मरीज की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

बताया जा रहा है कि, कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट के अब तक दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में दस्तक दे दी है। भारत के अलावा कुछ एशियाई देशों में इस वायरस के पेशेंट मिल चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ओमीक्रोन के आगे फैलने की चेतावनी दी है। डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है।

दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले इस वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति की पहचान हुई थी।कोविड-19 वायरस के बी.1.1.529 स्वरूप की पहचान दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को इस स्वरूप को 'चिंता उत्पन्न करने वाले स्वरूप' की श्रेणी में डाला। विश्व निकाय ने वायरस के इस स्वरूप को 'ओमीक्रॉन' नाम दिया है। इस वायरस की सबसे पहले जानकारी 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में मिली थी।

हाई कोर्ट ने थपथपाई पीठ...!

मुंबई की डॉक्टर ने अनजान छात्रा की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया

मुंबई : मुंबई के लोअर परेल में रहने वाली एक डॉक्टर की इंसानियत की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खूब सराहना की है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने अपने आदेश में डॉ. सोनल चौहान की प्रशंसा की है। डॉ. सोनल ने लखनऊ बेंच में एक हलफनामा दाखिल करके आईआईटी बीएचयू में दाखिला लेने वाली एक छात्रा की पढ़ाई का पूरा खर्च देने की बात कही है।

डॉ. सोनल की तरफ से लखनऊ बेंच में पैरवी करने वाले वकील अमित जायसवाल ने बताया कि वह अपने मुवक्किल से कभी मिले नहीं हैं, लेकिन यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसीलिए वह हाई कोर्ट में डॉ. सोनल की तरफ से पैरवी करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

वकील जायसवाल ने बताया कि जिस समय आईआईटी बीएचयू में दाखिला पाने वाली छात्रा संस्कृति रंजन की याचिका पर सुनवाई चल रही थी, उस समय वह कोर्ट में उपस्थित थी। जब उसे पता चला कि मुंबई की एक डॉक्टर उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करना चाहती हैं, तो वह भावुक हो गई और डॉक्टर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। वकील जायसवाल ने कहा, 'सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि छात्रा की पढ़ाई का खर्च वहन करने को लेकर आईआईटी के कई पूर्व छात्रों ने संपर्क किया है। इतना ही नहीं, कई वकील भी याचिकाकर्ता की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए आगे आए हैं।'

याचिकाकर्ता संस्कृति ने आर्थिक संकट के चलते फीस नहीं जमा कर पाने के कारण आईआईटी बीएचयू में अपनी सीट गंवाने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने आईआईटी बीएचयू को ऐडमिशन देने का निर्देश दिया था और न्यायमूर्ति सिंह ने सीट आवंटन के लिए 15 हजार रुपये खुद दिए थे।

ठाणे में 1 करोड़ 36 हजार 649 लोगों का टीकाकरण

मुंबई : ठाणे जिले ने शनिवार को कोरोना निवारक टीकाकरण अभियान में एक करोड़ खुराक का मील का पत्थर पार कर लिया है। कोविन पोर्टल के अनुसार, शाम 5.30 बजे तक 44,000 लोगों को टीका लगाया गया था। इसलिए जिले में अब तक कुल डोजों की संख्या 1 करोड़ 36 हजार 649 है। ठाणे जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन पर स्वास्थ्य व्यवस्था को बधाई दी और टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं जानकारी के अनुसार जिले में अब तक पहली खुराक 60 लाख 61 हजार 648 नागरिकों को और दूसरी खुराक 39 लाख 75 हजार नागरिकों को दी जा चुकी है ठाणे जिला पिछले कुछदिनों से टीकाकरण में अग्रणी रहा है।रोजाना 50 हजार तक टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही पूरे जिले में प्रतिदिन 450 से 500 टीकाकरण केंद्रों का आयोजन किया जा रहा है।

बिस्तर पर आघाड़ी सरकार-नारायण राणे

मुंबई : केंद्रीय लघु, सुक्ष्म व मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार पूरी तरह से बिस्तर पर ही है। यह सरकार बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रही है, जिसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। नारायण राणे ने मुंबई में शनिवार को पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार के निकम्मेपन की वजह से हर वर्ग परेशान है। राज्य में विकास के हर काम ठप हैं। इसके विपरीत केंद्र सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। उन्होंने अपने विभाग के काम के लिए कई राज्यों का दौरा भी किया है। महाराष्ट्र में उनके विभाग से अधिक से अधिक लोगों को उद्योग धंधे मिल सकें, इसका प्रयास जारी है। नारायण राणे ने शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि पता ही नहीं चलता कि वे शिवसेना में हैं या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में । संजय राउत दिल्ली में हमेशा शरद पवार के घर में ही पाए जाते हैं। संजय राउत देश को दिशा देने की बजाय सिर्फ झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं।

वर्क फ्रॉम होम पर मुंबई पुलिस का अलर्ट

रोजगार की आड़ में बढ़े सायबर ठगी के मामले, लुभावने मैसेज से दूर रहने की सलाह

मुंबई : लॉकडाउन के बाद से बेरोजगारों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है. हर व्यक्ति रोजी-रोटी के लिए यहां-वहां नौकरी खोजने में लगा हुआ है। इसी भागम भाग की वजह से कई लोगों को ठगी का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए मुंबई पुलिस की सायबर अपराध शाखा ने अलर्ट जारी किया है. लोगों को ऐसे लुभावने मैसेज से सावधान रहने की सलाह दी गई है। मोबाइल पर वर्क फ्रॉम होम का मैसेज आने पर उस पर कोई रिप्लाई न करने की सलाह दी है। पैसे ज्यादा देने का लालच देकर लोगों के साथ ठगी की जा सकती है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल पर wa.me/ मोबाइल नंबर लिखकर लिंक भेजा जाता है। जिसमें वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम, फूल टाइम लिखकर 9 हजार से 20 हजार तक सैलरी देने की बात कही जाती है। जिस पर क्लिक कर पूरा डिटेल्स मांगा जाता है। जिसके बाद फिर लिंक भेजी जाती है। साथ ही क्यूआर कोड भेजा जाता है जिससे पैसे मंगाए जाते हैं।

एक बार पैसे लेने के बाद टेलीग्राम की लिंक भेजी जाती है। अलग-अलग वेबसाइट के जरिये खरीदी कर ज्यादा रिटर्न बैक का ऑफर दिया जाता है। कैश बैक पर मिलने वाला पैसा वर्चुअल माध्यम में दिखता था। लेकिन वह पैसा उनका नहीं होता था। क्यूआर कोड के जरिये पैसे लेने की प्रक्रिया जारी रहती है। पुलिस के अनुसार आरोपी अलग अलग लोभ देकर कैश बैक में पैसे ऐड कर लेते थे। जिसके बाद जब कोई पैसे निकालने की कोशिश करता है उसके सामने अड़ंगा लगा दिया जाता है। जिससे वह पैसे न निकाल पाए। बाद में पता चलता था कि उनके साथ ठगी हुई है। इसके बाद आरोपी फिर से उन्हें संपर्क करते हैं और थोड़े पैसे खर्च कर उनके पैसे उन्हें लौटाने की लालच देते हैं। बेरोजगारों के साथ ज्यादातर इस प्रकार से ठगी की जाती है। सायबर पुलिस ने सलाह दी है कि मोबाइल पर आए किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक ना करें। नौकरी मिलने के लिए ऑनलाइन अर्जी करते वक्त उपयुक्त सावधानियां बरतें। वाट्सअप पर आए अज्ञात व्यक्ति के मैसेज की रिप्लाइ न करें। अज्ञात ग्रुप में जोड़े जाने पर तुरंत उसे छोड़कर रिपोर्ट करें। किसी भी प्रकार का अनजान नंबर से आये बारकोड को स्कैन न करें। किसी भी प्रकार के लोभ में न आएं। किसी भी प्रकार के वर्क फ्रॉम होम के विज्ञापन के लोभ में न आएं, अगर ऐसा दिखता है, तो उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उसकी जानकारी हासिल करें।

मुंबई पुलिस से मिले आंकड़े के मुताबिक मुंबई में जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक नौकरी से जुड़े धोखाधड़ी के कुल 86 मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि इनमें से 13 मामलों को सुलझाया गया है। जो दर्ज हुए अपराध का कुल सोलह प्रतिशत के लगभग है। वही। इन मामलों में अब तक 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मुंबई में गरजे ओवैसी ने मुसलमानों से पूछा-'पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म से क्या मिला? इसमें न फंसे'

मुंबई : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को मुसलमानों को राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता में न फंसने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म को न मानता था और न कभी मानूंगा. मैं उस सेक्युलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है. ओवैसी ने मुस्लिमों को सियासी सेक्युलरिज्म से बचने की सलाह दी है.

मुंबई में तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ह्लमैं देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि हमें सेक्युलरिज्म से क्या मिला? क्या हमें सेक्युलरिज्म से आरक्षण मिला? क्या मस्जिद गिराने वालों को सजा मिली? क्या सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर हमें इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली... नहीं मिली. किसी को कुछ नहीं मिला. मैं उस सेक्युलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है.

मैं पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म को नहीं मानता. मैं सभी से राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता में नहीं फंसने की अपील करता हूं.' उन्होंने कहा, 'सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में ग्रेजुएट मुस्लिम केवल 4.9 फीसदी हैं. मिडिल स्कूल में केवल 13 फीसदी मुस्लिम छात्र हैं. महाराष्ट्र में 83 फीसदी मुस्लिम भूमिहीन हैं.' उन्होंने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा और कहा कि अगर सरकार मुसलमानों को आरक्षण देती तो मुस्लिम बच्चों को शिक्षा मिलती.

महाराष्ट्र एटीएस : प्रतिबंधित आईआरएफ की गतिविधियों में लिप्त शख्स पर यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई

मुंबई : विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर केंद्र द्वारा प्रतिबंध को पांच साल और बढ़ाने के मद्देनजर महाराष्ट्र एटीएस ने शनिवार को कहा कि इस संगठन से सक्रिय रूप से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर सख्त आतंकवाद विरोधी कानून का आरोप लगाया जाएगा। एक अखबार में जारी विज्ञापन में एटीएस ने कहा कि आईआरएफ की गतिविधियों में हिस्सा लेने, चंदा इकट्ठा करने या उसका सदस्य बनने पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत आरोप लगाया जाएगा। जिसके पास इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) की सदस्यता है,

वह रैलियों में भाग लेता है, रैली को एकत्र करता है या उन्हें दान देता है या संगठन के उद्देश्य को प्रचारित करने में मदद करता है, वह व्यक्ति यूएपीए की धाराओं के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। केंद्र सरकार ने इस साल नवंबर में आईआरएफ पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया था। आईआरएफ को पहली बार 17 नवंबर, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था।

यह समाचार पत्र मासिक महाराष्ट्र क्राईम्स मालिक,मुद्रक प्रकाशक सिराज चौधरी द्वारा राजीव प्रिंटर्स,४९६,पंचशील नगर-१, नागसेन बुद्ध मंदिर रोड नं-३, तिलक नगर, चेम्बुर,मुंबई-४०००८९ से मुद्रित करवा कर ८/ऐ/१६९/२७०२/टागोर नगर, विक्रोली (पू),मुंबई-४०००८३ से प्रकाशित किया ।

संपादक- सिराज चौधरी मो. ९७७३६२२९६७